भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2456

दिनांक 10 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

.....

ओडिशा में जल निकायों का पुनरुद्धार

2456. श्री दिलीप राय:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ओड़िशा में पारंपरिक तालाबों और जल निकायों के पुनरुद्धार में सहायता कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) आज की तिथि तक कितने जल निकायों का पुनरुद्धार किया गया है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ग): जी, हां। भारत सरकार विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करते हुए ओडिशा सहित देश भर में पारंपरिक तालाबों और जल निकायों का पुनरुद्धार करने में समर्थन कर रही है। योजना/कार्यक्रम-वार विवरण इस प्रकार हैं;

1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

वर्ष 2015-16 में, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को खेत पर पानी की वास्तविक उपलब्धता बढ़ाने और सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, खेत पर जल उपयोग दक्षता में सुधार, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को अपनाने आदि के उद्देश्य से शुरू किया गया था। पीएमकेएसवाई के हर खेत को पानी (एचकेकेपी) घटक के अंतर्गत जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

पीएमकेएसवाई 2.0 (वर्ष 2021-26) के तहत, पारंपरिक तालाबों और जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26) के दौरान ओडिशा सरकार को 162.875 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में 433 पारंपरिक तालाबों और जल निकायों का पुनरुद्धार हुआ है।

2. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

भारत सरकार अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 के अंतर्गत जल निकायों का पुनरुद्धार करने में भी समर्थन कर रही है।

अमृत 2.0 के तहत, जल निकायों का पुनरुद्धार करने के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26) के दौरान ओडिशा सरकार को 621.46 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में 27 जल निकायों का पुनरुद्धार हुआ है।

3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)

भारत सरकार देश भर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) कार्यान्वित कर रही है, जिसके अंतर्गत पारंपरिक जल निकायों का नवीकरण, अनुमत कार्य की श्रेणियों में से एक है।

मनरेगा के अंतर्गत, पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26) के दौरान ओडिशा राज्य में पारंपरिक जल निकायों के 19,131 पुनरुद्धार कार्य पूरे किए गए हैं, जिसमें 1,045.23 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

4. जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर)

वर्ष 2019 में, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल शक्ति अभियान (जेएसए) शुरू किया गया, इसके बाद, वर्ष 2021 में, माननीय प्रधान मंत्री द्वारा जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान "कैच द रेन: व्हेयर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स" विषय के साथ शुरू किया गया। तब से, यह अभियान विभिन्न हितधारकों के बीच स्थानीय कार्रवाई और अभिसरण (कन्वर्जेंस) के माध्यम से जल संरक्षण और जल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है।

जेएसए-सीटीआर 2025 को "जल संचय - जन भागीदारी: जन जागरूकता की ओर" विषय के साथ लॉन्च किया गया था, जो जमीनी स्तर पर गहन रूप से सहभागिता, अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण (कन्वर्जेंस) और नए वित्तपोषण तंत्र पर बल देता है।

जेएसए: सीटीआर अभियान के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों के दौरान ओडिशा में पारंपरिक जल निकायों के 25,253 पुनरुद्धार कार्य पूरे किए गए हैं।

*****